AIBE XXII

1. **भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नांकित किस मामले में घोषित किया कि संविधान की प्रस्तावना भारतीय संविधान का अंग है एवं अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधित किया जा सकता है?**
   (a) रिबेरुबारी केस
   (b) केशवानन्द भारती केस
   (c) गोलकनाथ केस
   (d) एस. आर. बोम्मई केस

2. **निम्नलिखित में से किसने कहा है कि "भारतीय संविधान एक सशक्त केन्द्रीयकृत प्रवृत्ति वाला परिसंघात्मक संविधान है"?**
   (a) के० सी० व्हेयर ने
   (b) ए० वी० डायसी ने
   (c) सर आइवर जैनग्स ने
   (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

3. **संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है?**
   (a) अनुच्छेद 3
   (b) अनुच्छेद 4
   (c) अनुच्छेद 5
   (d) अनुच्छेद 368

4. **एक व्यक्ति जो या जिसका पिता भारत के राज्यक्षेत्र में पैदा नहीं हुआ था, लेकिन "(क) जिसका 'भारत के राज्यक्षेत्र में अपना अधिवास है, और (ख) जो आमतौर पर संविधान के प्रारंभ होने से ठीक पहले के कम-से-कम 5 वर्ष के लिए भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर' रहा हो" उसे भारतीय नागरिक के रूप में माना जाता है। यह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है?**
   (a) अनुच्छेद 5
   (b) अनुच्छेद 5(b)
   (c) अनुच्छेद 5(a)
   (d) अनुच्छेद 5(c)

5. **"प्रजातंत्र हेतु वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अपरिहार्य है" स्थापित किया गया:**
   (a) ए. के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य में
   (b) रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य में
   (c) एन. बी. खरे बनाम पंजाब राज्य में
   (d) मद्रास राज्य बनाम वी.जी. रॉ में

6. **नागरिकों के पिछड़े वर्गों तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के पक्ष में शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के मामलों में आरक्षण लागू किया जा सकता है**
   (a) सरकारी सहायता प्राप्त निजी अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में
   (b) गैर - सहायता प्राप्त निजी अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में
   (c) गैर - सहायता प्राप्त निजी शिक्षण संस्थानों में
   (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

7. **निम्नलिखित में से कौन 'राज्य के नीति निदेशक सिद्धान्तों' का भाग नहीं है ?**
   (a) समान न्याय एवं नि:शुल्क विधिक सहायता
   (b) न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण
   (c) संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार
   (d) ग्राम पंचायतों का संगठन

8. **कौन-सा अनुच्छेद 'सहकारी समितियों की प्रोन्नति' से संबंधित है?**
   (a) 39A (b) 43A
   (c) 43B (d) 48A

9. **संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम द्वारा, मौलिक कर्तव्यों के अध्याय को संविधान में अध्याय IV-A के रूप में जोड़ा गया है?**
   (a) 40वां संशोधन अधिनियम
   (b) 42वां संशोधन अधिनियम
   (c) 45वां संशोधन अधिनियम
   (d) 49वां संशोधन अधिनियम

10. **भारत के राष्ट्रपति:**
    (a) निर्वाचित होता है
    (b) नियुक्त होता है
    (c) चयनित होता है
    (d) नामांकित होता है

11. **भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल है :**
    (a) पाँच वर्ष
    (b) बासठ वर्ष तक
    (c) पैंसठ वर्ष तक
    (d) छ: वर्ष

12. **कोई व्यक्ति संसद का सदस्य होने के लिए अयोग्य है यदि वह**
    (a) भारत में किसी अपराध हेतु दोषसिद्ध हो
    (b) संसद द्वारा निर्मित किसी विधि द्वारा या उसके अंतर्गत अनर्ह हो
    (c) सरकार को आवश्यक करों, राजस्व या वैधानिक शुल्कों का भुगतान करने में विफल रहा हो
    (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

13. **आपात की उद्घोषणा के दौरान, लोकसभा की अवधि में अभिवृद्धि की जा सकेगी**
    (a) एक बार में 6 माह से अनधिक अवधि के लिए
    (b) एक बार में 1 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए
    (c) एक बार में 2 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए
    (d) एक बार में 3 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए

14. **निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?**
    संसद सदस्य की अयोग्यता के प्रश्न पर निर्णय लेने में, राष्ट्रपति कार्य करेगा:
    (a) चुनाव आयोग की राय के अनुसार
    (b) सुप्रीम कोर्ट की राय के अनुसार
    (c) मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से
    (d) अपने विवेक से

15. **संसदीय समिति का अर्थ उस समिति से है जो,**
    (a) सदन द्वारा नियुक्त है।
    (b) सदन द्वारा नामित है ।
    (c) सदन द्वारा निर्वाचित है ।
    (d) यह सभी

16. **अध्यादेश जारी करने के लिए भारत के राष्ट्रपति की शक्ति एक / एक है-**

JGP (Judiciary Guidance Program) - Click Now to Enroll
AIBE Study Materials – Click here to Buy now
AGP (Advocacy Guidance Program)- Click Now to Enroll
AIBE 22 Guidance Program- Click Now to Enroll

(a) वैधानिक शक्ति
(b) कार्यकारिणी शक्ति
(c) अर्ध-न्यायिक शक्ति
(d) न्यायिक शक्ति

17. भारत के राज्यक्षेत्र के सभी सिविल और न्यायिक प्राधिकारी उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य करेगें।
(a) सही
(b) गलत
(c) आंशिक रूप से सही, आंशिक रूप से गलत
(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

18. उच्चतम न्यायालय की आनुषंगिक शक्तियाँ किस अनुच्छेद के अन्तर्गत आती है?
(a) अनुच्छेद 138
(b) अनुच्छेद 139
(c) अनुच्छेद 140
(d) अनुच्छेद 147

19. लोक लेखा समिति के सदस्य होते हैं:
(a) लोकसभा के बाईस सदस्य
(b) राज्यसभा के बाईस सदस्य
(c) लोकसभा के पन्द्रह सदस्य और राज्यसभा के सात सदस्य
(d) लोकसभा के सात सदस्य और राज्यसभा के पन्द्रह सदस्य

20. भारत का नियंत्रक और महालेखापरीक्षक संघ के खातों से सम्बन्धित अपनी रिपोर्ट जमा करेगा-
(a) लोक लेखा समिति को
(b) संसद को
(c) राष्ट्रपति को
(d) वित्तमंत्री को

21. किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है?
(a) अनुच्छेद 200
(b) अनुच्छेद 206
(c) अनुच्छेद 210
(d) अनुच्छेद 212

22. विधानमंडल का सत्रावसान का अधिकार किसको है?
(a) मुख्यमंत्री
(b) स्पीकर
(c) राष्ट्रपति
(d) राज्यपाल

23. भारत के संविधान के अन्तर्गत किसी राज्य के विधान मण्डल के किसी सदन का सदस्य, ...की अवधि तक सदन की अनुज्ञा के बिना उसके सभी अधिवेशनों से अनुपस्थित रहता है तो सदन उसके स्थान को रिक्त घोषित कर सकेगा।
(a) 120 दिन
(b) 90 दिन
(c) 60 दिन
(d) 30 दिन

24. विधानमंडल के प्रत्येक सदन के दो सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल होता है
(a) तीन माह
(b) चार माह
(c) छः माह
(d) बारह माह

25. संविधान के किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालय रिट जारी करने की शक्ति रखते हैं?
(a) अनुच्छेद 32 (b) अनुच्छेद 136
(c) अनुच्छेद 226 (d) अनुच्छेद 224

26. उच्चतम न्यायालय का अधिकार क्षेत्र उच्च न्यायालय से अधिक व्यापक है
(a) सही
(b) गलत
(c) केवल कुछ दशाओं में
(d) दोनों का एक समान अधिकार क्षेत्र है

27. कौन-सी समिति पंचायती राज संस्था से सम्बन्धित है?
(a) मुधोलकर समिति
(b) बलवंत राय मेहता समिति
(c) मलीमथ समिति
(d) खुल्लर समिति

28. पंचायतों के गठन से संबंधित भारतीय संविधान का .... है:
(a) अनुच्छेद 243-ख
(b) अनुच्छेद 243-ण
(c) अनुच्छेद 243- ब
(d) अनुच्छेद 243-क

29. बिहार राज्य बनाम कामेश्वर सिंह का वाद निम्नलिखित में से किस सिद्धांत से संबंधित है?
(a) मूल संरचना का सिद्धांत
(b) आच्छादन का सिद्धांत
(c) सार और तत्व का सिद्धांत
(d) छद्मता का सिद्धांत

30. भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची में उल्लिखित विषय पर विधि बनाने का अधिकार देता है?
(a) अनुच्छेद 245
(b) अनुच्छेद 249
(c) अनुच्छेद 251
(d) अनुच्छेद 253

31. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 279 किसको परिभाषित करता है?
(a) पेशे पर कर
(b) शुद्ध आगम आदि की गणना
(c) वित्त आयोग
(d) संघ से कुछ राज्यों को अनुदान

32. के संविधान का कौन-सा भाग वित्त, संपत्ति, अनुबंध और वाद (सूट) से सम्बन्धित है-
(a) भाग-XII
(b) भाग-XIII
(c) भाग-XVII
(d) भाग-XIX

JGP (Judiciary Guidance Program) - Click Now to Enroll
AIBE Study Materials – Click here to Buy now
AGP (Advocacy Guidance Program)- Click Now to Enroll
AIBE 22 Guidance Program- Click Now to Enroll

33. संविधान का कौनसा अनुच्छेद 'माल व सेवा कर परिषद' की स्थापना का प्रावधान करता है?
(a) अनुच्छेद 269A
(b) अनुच्छेद 270
(c) अनुच्छेद 279A
(d) अनुच्छेद 279

34. वित्त आयोग में शामिल हैं।
(a) पाँच सदस्य
(b) चार पूर्ण-कालिक सदस्य
(c) एक अध्यक्ष और चार सदस्य
(d) एक अध्यक्ष और तीन अन्य सदस्य

35. संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करते हुए किए गए सभी सरकारी अनुबंधों को राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित के तहत किया जाना व्यक्त किया जाएगा:
(a) भारत के संविधान का अनुच्छेद 297
(b) भारत के संविधान का अनुच्छेद 280
(c) भारत के संविधान का अनुच्छेद 299
(d) इनमें से कोई भी नहीं

36. संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत कोई राज्य राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से अंतर्राज्यीय व्यापार पर कर लगा सकता है?
(a) अनुच्छेद 302 (b) अनुच्छेद 303(1)
(c) अनुच्छेद 303(2) (d) अनुच्छेद 304

37. भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 'लोक सेवा आयोगों के कृत्यों का विस्तार करने की शक्ति' सम्बन्धी प्रावधान किये गए हैं?
(a) अनुच्छेद 321 (b) अनुच्छेद 322
(c) अनुच्छेद 323 (d) अनुच्छेद 324

38. राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को कदाचार के आधार पर तभी हटाया जा सकता है जब उसके द्वारा जांच की गई हो-
(a) भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा इसे संदर्भित किए जाने पर
(b) राज्यपाल के द्वारा उच्च न्यायालय के माध्यम से
(c) के अध्यक्ष द्वारा
(d) संयुक्त संसदीय समिति द्वारा

39. प्रशासकीय प्राधिकरण अधिनियम, 1985 के अन्तर्गत राज्य प्रशासकीय प्राधिकरण का गठन कौन कर सकता है?
(a) भारत का राष्ट्रपति
(b) उच्चतम न्यायालय
(c) संसद
(d) सम्बन्धित राज्य सरकार

40. प्रशासनिक न्यायाधिकरण के लिए प्रावधान भारत के संविधान में .... संशोधित द्वारा जोड़ा गया है।
(a) 42nd (b) 44th
(c) 36th (d) 78th

41. संविधान का अनुच्छेद 329 संबंधित है-
(a) संसद की संशोधन शक्ति
(b) संसद की कर सम्बन्धी शक्ति
(c) निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन
(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

42. निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई?
(a) 48 वें (b) 57 वें
(c) 61 वीं (d) 63 वें

43. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 340 से सम्बन्धित है-
(a) पिछड़ा वर्ग आयोग
(b) निर्वाचन आयोग
(c) यू० पी० एस० सी०
(d) वित्त आयोग

44. राज्य के राज्यपाल द्वारा राज्य विधान सभा में ऐंग्लो इण्डियन समुदाय से कितने प्रतिनिधि को नामित किया जा सकता है?
(a) तीन (b) दो
(c) एक (d) किसी को नहीं

45. भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन-सी एक संघ की भाषा है?
(a) बुंदेली लिपि में हिंदी
(b) देवनागरी लिपि में हिंदी
(c) हिंदी और अंग्रेजी दोनों
(d) केवल हिंदी न कि अंग्रेजी

46. किस आपातकाल की स्थिति में, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत दिये गये मूल स्वतंत्रताओं को निलम्बित किया जा सकता है?
(a) राज्य में संवैधानिक प्रणाली के विफल होने पर
(b) आंतरिक सशस्त्र विद्रोह होने पर
(c) वित्तीय आपातकाल पर
(d) युद्ध अथवा बाह्य हमला होने पर

47. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में निहित है-
(a) निर्वाचन आयोग
(b) वित्त आयोग
(c) आपातकाल की उद्घोषणा
(d) संघ लोक सेवा आयोग

48. 'पूर्ण विश्वास और क्रेडिट' का सिद्धांत भारतीय संविधान के अनुच्छेद .... में निहित है।
(a) 261 (b) 368
(c) 148 (d) 256

49. निम्नलिखित मामलों में से किसमें न्याय के बहुमत की सहमति थी कि संविधान का मूल ढाँचा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत शक्ति के अभ्यास में संविधान-संशोधन द्वारा, नष्ट या क्षतिग्रस्त नहीं किया जा सकता?
(a) वामन राव बनाम भारतीय संघ
(b) गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य
(c) कुलदीप नैयर बनाम भारत संघ
(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

50. भारत के संविधान का अनुच्छेद 371 ग राज्य के संबंध में विशेष उपबन्ध से सम्बन्धित है।
(a) नागालैण्ड
(b) मणिपुर
(c) असम
(d) आन्ध्र प्रदेश

JGP (Judiciary Guidance Program) - Click Now to Enroll
AIBE Study Materials – Click here to Buy now
AGP (Advocacy Guidance Program)- Click Now to Enroll
AIBE 22 Guidance Program- Click Now to Enroll

All India Bar Examination XXII Practice Set

उत्तर कुंजी

Q. No.	Ans.	Q. No.	Ans.	Q. No.	Ans.	Q. No.	Ans.	Q. No.	Ans.
1.	[B]	11.	[A]	21.	[A]	31.	[B]	41.	[C]
2.	[C]	12.	[B]	22.	[D]	32.	[A]	42.	[C]
3.	[A]	13.	[B]	23.	[C]	33.	[C]	43.	[A]
4.	[D]	14.	[A]	24.	[C]	34.	[C]	44.	[C]
5.	[B]	15.	[D]	25.	[C]	35.	[C]	45.	[B]
6.	[B]	16.	[A]	26.	[B]	36.	[D]	46.	[D]
7.	[C]	17.	[A]	27.	[B]	37.	[A]	47.	[C]
8.	[C]	18.	[C]	28.	[A]	38.	[A]	48.	[A]
9.	[B]	19.	[C]	29.	[D]	39.	[C]	49.	[A]
10.	[A]	20.	[C]	30.	[B]	40.	[A]	50.	[B]

AIBE 22
Guidance Program
(Live + Recorded)
This is a smart, Bare Acts–based program designed with a single-minded goal
Crack the AIBE (All India Bar Examination)
Linking Support
988 774 6465 (Classes)
773 774 6465 (Publication)
Scan this QR
Enrol Now or visit
linkinglaws.classx.co.in

Scan this QR
Course Brochure
Live Classes
Recorded Classes
6 Months Validity
Study Material Access
Full Mock Test
Practice Test Series
www.LinkingLaws.com

JGP (Judiciary Guidance Program) - Click Now to Enroll
AIBE Study Materials – Click here to Buy now
AGP (Advocacy Guidance Program)- Click Now to Enroll
AIBE 22 Guidance Program- Click Now to Enroll

1. **Ans. [B]**
लिंकिंग प्रावधान- उद्देशिका L/w अनुच्छेद 368 भारत का संविधान।
स्पष्टीकरण- भारत के संविधान की उद्देशिका इसके निर्माताओं के आशय, इसके निर्माण के पीछे के इतिहास और राष्ट्र के मूल मूल्यों और सिद्धांतों को प्रस्तुत करती है। संविधान का हिस्सा होने के नाते उद्देशिका पर सर्वोच्च न्यायालय में कई बार चर्चा हुई है। इसे निम्नलिखित दो मामलों को पढ़कर समझा जा सकता है-
(1) **री बेरुबारी मामला (1960) में –** न्यायालय ने कहा कि 'प्रस्तावना निर्माताओं के दिमाग को खोलने की कुंजी है' लेकिन इसे संविधान का हिस्सा नहीं माना जा सकता है।
(2) **केशवानंद भारती मामला (1973) –** इस मामले में, न्यायालय ने माना कि संविधान की प्रस्तावना को अब संविधान का हिस्सा माना जाएगा और संविधान के एक हिस्से के रूप में, इसे अनुच्छेद 368 के तहत संशोधित किया जा सकता है।

2. **Ans. [C]**
स्पष्टीकरण:- सर इवोर जेनिंग्स भारत को "मजबूत केंद्रीकृत प्रवृत्तियों वाला संघ" मानते थे।

3. **Ans. [A]**
लिंकिंग प्रावधान :-
1. **अनुच्छेद 2 -** नये राज्यों का प्रवेश।
2. **अनुच्छेद 4 -** अनुच्छेद 2 व 3 में नये राज्य का प्रवेश या निर्माण के प्रभाव से अनुसूची 1 व 4 में परिवर्तन पर अनुच्छेद 368 लागू नहीं।
3. **अनुसूची 1 -** राज्य व संघ राज्यक्षेत्रो की सूची।
4. **अनुसूची 4 -** राज्य सभा में स्थानों का अवंटन ।
5. **अनुच्छेद 368 -** संविधान में संशोधन की प्रक्रिया।

स्पष्टीकरण - अनुच्छेद 3- संसद विधि द्वारा नये राज्यों का निर्माण कर सकेगी, किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा, घटा सकेगी, सीमाओं में परिवर्तन, राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकेगी।

4. **Ans. [D]**
लिंकिंग प्रावधान :- अनुच्छेद 5 COI.
स्पष्टीकरण – अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता से संबंधित है। अनुच्छेद 5 (ग) में कहा गया है कि इस संविधान के प्रारंभ पर, प्रत्येक व्यक्ति जिसका भारत के राज्यक्षेत्र में अधिवास है और ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले कम से कम पाँच वर्ष तक भारत के राज्यक्षेत्र में मामूली तौर से निवासी रहा है, भारत का नागरिक होगा ।

5. **Ans. [B]**
लिंकिंग प्रावधान- अनुच्छेद 19 L/w 14, 21, 358, 359 भारत का संविधान।
स्पष्टीकरण- अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आदि के संबंध में कुछ अधिकारों की सुरक्षा से संबंधित है। अनुच्छेद 19(1) में प्रावधान है कि सभी नागरिकों को यह अधिकार होगा-
(क) भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता;
(ख) शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के इकट्ठा होना;
(ग) संघ या यूनियन बनाना;
(घ) भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमना;
(ड़) भारत के क्षेत्र के किसी भी हिस्से में निवास और बसना;
(च) 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा छोड़ा गया। (संपत्ति अर्जित करना, धारण करना और निपटान करने का अधिकार);
(छ) कोई भी पेशा अपनाना, या कोई व्यवसाय, व्यापार या कारोबार करना।

निर्णय विधि- रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य (1950) में, सर्वोच्च न्यायालय ने प्रेस की स्वतंत्रता को वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक हिस्सा घोषित किया है। इसने आगे कहा कि लोकतंत्र में वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अपरिहार्य है।

AIBE BARE ACTS COMBO SET©
Comprehensive Study Package
Study Materials (Major & Minor Laws inc. other Study Material
Diglot Edition
English Edition
You can carry these Bare Act in Exam Hall for AIBE
Linking Support
988 774 6465 (Classes)
773 774 6465 (Publication)
Scan this QR Order Now or visit www.LinkingLaws.com
Link Provision | Section Switching Table
illustration Table | Bracket Presentation
Amendment Analysis | Key Words of Section
www.LinkingLaws.com

JGP (Judiciary Guidance Program) - Click Now to Enroll
AIBE Study Materials – Click here to Buy now
AGP (Advocacy Guidance Program)- Click Now to Enroll
AIBE 22 Guidance Program- Click Now to Enroll

6. **Ans. [B]**
लिंकिंग प्रावधान- अनु.15 L/w अनु.16, 21A, 30, 41, 45, 46, 51क(ट), 337COI ।
स्पष्टीकरण- अनु.15 धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव के निषेध से संबंधित है। अनु.15(6) को 103वें संशोधन अधिनियम, 2019 द्वारा अन्तः स्थापित किया गया था। यह राज्य को अनु.15(4), (5) में उल्लिखित लोगों के अलावा किसी भी नागरिक के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान करने में सक्षम बनाता है। यह आगे प्रावधान करता है कि निजी शैक्षणिक संस्थानों सहित शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण के संबंध में विशेष प्रावधान प्रत्येक श्रेणी में कुल सीटों के मौजूदा अधिकतम 10% के अतिरिक्त होंगे।

7. **Ans. [C]**
लिंकिंग प्रावधान- भाग 4 (अनु.36-51), अनु.73 L/w अनु.162 COI
स्पष्टीकरण- भाग 4 (अनु.36-51) राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। इन्हें आयरिश संविधान से अपनाया गया है, और अपने लोगों को सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। दिए गए प्रश्न में, विकल्प ए, बी और डी निर्देशक सिद्धांत हैं, जबकि अनु.73 संघ की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार से संबंधित है।
अनु.39क- समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता।
अनु.40- ग्राम पंचायतों का संगठन।
अनु.50- न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण।

8. **Ans. [C]**
लिंकिंग प्रावधान- अनु.43 ख L/w भाग IX ख COI।
स्पष्टीकरण- अनु.43 ख सहकारी समितियों के संवर्धन से संबंधित है। यह 97वें संशोधन अधिनियम, 2011 द्वारा (15/02/2012 से प्रभावी) अन्तः स्थापित की गयी थी। यह गांधीवादी विचारधारा पर आधारित है। यह प्रावधान करता है कि राज्य सहकारी समितियों की स्वैच्छिक विरचना, उनके स्वशासी कार्यकरण, लोकतांत्रिक नियंत्रण और वृत्तिक प्रबंधन का संवर्धन करने का प्रयास करेगा।

9. **Ans. [B]**
लिंकिंग प्रावधान :-
1. **अनुच्छेद 51क -** मौलिक कर्तव्य - कुल 11 ।
2. 86वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2002
3. **भाग 4क -** स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर समाहित किया गया।
4. **मूल कर्तव्यों का स्रोत -** USSR का संविधान।

स्पष्टीकरण - भाग 4क (अनुच्छेद 51क) को संविधान (बयालीसवं संशोधन) अधिनियम, 1976, द्वारा समाहित किया गया।

10. **Ans. [A]**
लिंकिंग प्रावधान:-
1. **अनुच्छेद 52** – भारत का एक राष्ट्रपति होगा।
2. **अनुच्छेद 53-60** – राष्ट्रपति की नियुक्ति तथा उसके सम्बन्ध में प्रक्रिया।
3. **अनुच्छेद 61** – राष्ट्रपति पर महाभियोग।
4. **अनुच्छेद 72** – राष्टपति द्वारा क्षमादान।
5. **अनुच्छेक 123** – राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां।

स्पष्टीकरण:- अनुच्छेद 55 (3)- राष्ट्रपति का निर्वचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा किया जायेगा तथा ऐसा निर्वाचन गुप्त मतदान द्वारा किया जायेगा।

11. **Ans. [A]**
लिंकिंग प्रावधान:- अनुच्छेद 63-71.
स्पष्टीकरण:- अनुच्छेद 64 - उपराष्ट्रपति पांच वर्ष तक पद पर रहता है। उपराष्ट्रपति को कितनी भी बार पुनः निर्वाचित किया जा सकता है। हालाँकि, कार्यालय को मृत्यु, इस्तीफे या निष्कासन से पहले समाप्त किया जा सकता है।

12. **Ans. [B]**
लिंकिंग प्रावधान- अनु. 102 L/w अनु. 84, 102, 173, 191, दसवीं अनुसूची COI ।
स्पष्टीकरण- अनु.102 सदस्यता के लिए निरर्हताओं से संबंधित है। यह प्रावधान करता है कि कोई व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य होने के लिए निरर्हित होगा यदि-
(क) वह भारत सरकार या राज्य सरकार के तहत लाभ का कोई पद धारण करता है;
(ख) वह विकृतचित्त है और सक्षम न्यायालय की ऐसी घोषणा विद्यमान है;
(ग) वह अनुन्मोचित दिवालिया है;
(घ) वह भारत का नागरिक नहीं है;
(ड) वह संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन निरर्हित है।

JGP (Judiciary Guidance Program) - Click Now to Enroll
AIBE Study Materials – Click here to Buy now
AGP (Advocacy Guidance Program)- Click Now to Enroll
AIBE 22 Guidance Program- Click Now to Enroll

13. Ans. [B]

लिंकिंग प्रावधान- अनु.83 L/w अनु.172, 352-355 COI।

स्पष्टीकरण- अनु.83 संसद के सदनों की अवधि से संबंधित है। यह प्रावधान करता है कि COS विघटन के अधीन नहीं होगा और HOP, यदि पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती है तो, अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से 5 वर्ष तक बनी रहेगी।

अनुच्छेद 83(2) का परन्तुक- इसमें कहा गया है कि जब आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है, तब संसद, विधि द्वारा ऐसी अवधि को **एक बार में 1 वर्ष से अनअधिक** की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है और उद्घोषणा के प्रवर्तन में न रह जाने के बाद उसका विस्तार किसी भी दशा में 6 मास की अविध से अधिक नहीं होगा।

14. Ans. [A]

लिंकिंग प्रावधान-. अनुच्छेद 103 L/w 102, 191, 192, 243F. 243V, 361B, 10th schedule COI.

स्पष्टीकरण- अनुच्छेद 103 सदस्यों की अयोग्यता के प्रश्नों पर निर्णय से संबंधित है। यह प्रावधान करता है कि यदि कोई प्रश्न w.r.t. संसद के किसी भी सदन के सदस्य की अयोग्यता उत्पन्न होने पर ऐसा प्रश्न राष्ट्रपति के निर्णय के लिए भेजा जाएगा और उनका निर्णय अंतिम होगा। लेकिन, ऐसे किसी भी प्रश्न पर कोई भी निर्णय देने से पहले राष्ट्रपति चुनाव आयोग की राय लेंगे और उस राय के अनुसार कार्य करेंगे।

15. Ans. [D]

लिंकिंग प्रावधान- अनु.79-81, 89, 93, 105, 118 COI।

स्पष्टीकरण- संविधान संसदीय समितियों, उनकी संरचना, कार्यकाल और कार्यों के संबंध में कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं करता है। सामान्य तौर पर,
इसका मतलब एक समिति है जो सदन द्वारा नियुक्त या निर्वाचित या अध्यक्ष / सभापति द्वारा नामित होती है और अध्यक्ष / सभापति के निर्देशन में काम करती है। संसदीय समितियों की उत्पत्ति ब्रिटिश संसद में हुई है। यह दो प्रकार की होती है-

(i) **स्थायी समितियाँ-** ये स्थायी होती हैं (हर साल या समय-समय पर गठित) और निरंतर आधार पर काम करती हैं।
(ii) **तदर्थ समिति-** ये अस्थायी होती हैं और उन्हें सौंपे गए कार्य के पूरा होने पर अस्तित्व में नहीं रहती हैं।

16. Ans. [A]

लिंकिंग प्रावधान :-

1. **अनुच्छेद 213 -** राज्यपाल की अध्यादेश जफि करने की शक्ति।
2. **अनुसूची 7 -** विधि बनाने के विषय वस्तु का वर्गीकरण।

स्पष्टीकरण - अनुच्छेद 123 - राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने की शक्ति वैधानिक शक्ति है, यह शक्ति राष्ट्रपति द्वारा तब प्रयोग की जाती है जब दोनों सदन सत्र में नहीं हो और किसी विषय पर विधि बनाना आवश्यक हो।

17. Ans. [A]

लिंकिंग प्रावधान:-

1. भारत के संविधान के **अनुच्छेद 144** में कहा गया है कि 'भारत के क्षेत्र में सभी प्राधिकरण, नागरिक और न्यायिक, सर्वोच्च न्यायालय की सहायता में कार्य करेंगे।'
2. भारतीय संविधान का **अनुच्छेद 157** राज्य के राज्यपाल की शक्तियों से संबंधित है।
3. भारतीय संविधान का **अनुच्छेद 137** सर्वोच्च न्यायालय के पुनर्विलोकन क्षेत्राधिकार से संबंधित है।
4. भारतीय संविधान का **अनुच्छेद 121** संसद में चर्चा पर प्रतिबंध से संबंधित है।

स्पष्टीकरण:- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 144 नागरिक और न्यायिक अधिकारियों को सर्वोच्च न्यायालय की सहायता के लिए कार्य करने की सलाह देता है। इसमें कहा गया है कि भारत के क्षेत्र में सभी प्राधिकरण, नागरिक और न्यायिक, सर्वोच्च न्यायालय की सहायता में कार्य करेंगे।

JUDICIARY GUIDANCE PROGRAM (JGP)
Live + Recorded Course
Complete Syllabus Coverage
Mock Test Series | SubjectWise Practice Set | Recorded Lectures | Practice & Revision Sessions | Expert Mentorship (Tansukh Sir) | Bilingual Classes
Linking Support
988 774 6465 (Classes)
773 774 6465 (Publication)
Scan this QR ENROL NOW

ADVOCACY GUIDANCE PROGRAM (JGP)
Validity - 03 Months
Complete Syllabus Coverage
Civil Court Practice | Criminal Court Practice | Cyber Law Practice | Dual Mode Learning | Legal Personality Development | Structured 3 Volumes
is available at Linking App.
Scan this QR ENROL NOW

JGP (Judiciary Guidance Program) - Click Now to Enroll
AIBE Study Materials – Click here to Buy now
AGP (Advocacy Guidance Program)- Click Now to Enroll
AIBE 22 Guidance Program- Click Now to Enroll

18. **Ans. [C]**

लिंकिंग प्रावधान:-

1. अनु. 140 सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियों से संबंधित है।
2. भारत के सर्वोच्च न्यायालय में भारत के मुख्य न्यायाधीश और अधिकतम 34 न्यायाधीश होते हैं।
3. इसकी स्थापना वर्ष 1950 में हुई थी।
4. भारत के संविधान द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की सीट दिल्ली घोषित की गई है।
5. अनुच्छेद 124(2)सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है।

हरिलाल जे. कानिया **भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश** थे।

स्पष्टीकरण:- अनुच्छेद 140 सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियों से संबंधित है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में भारत के मुख्य न्यायाधीश और अधिकतम 34 न्यायाधीश होते हैं।

19. **Ans. [C]**

स्पष्टीकरण: - लोक लेखा समिति का गठन हर साल अनधिक 22 सदस्यों की संख्या के साथ किया जाता है, जिनमें से 15 संसद के निचले सदन लोकसभा से होते हैं, और 7 संसद के ऊपरी सदन राज्यसभा से होते हैं।

20. **Ans. [C]**

लिंकिंग प्रावधान: अनुच्छेद 151 L/w 148, 149, 150, 279, 377 भारत का संविधान।

स्पष्टीकरण- अनुच्छेद 151 में प्रावधान है कि-

(1) संघ के खातों से संबंधित भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत की जाएगी, जो उन्हें संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा।

(2) किसी राज्य के लेखाओं से संबंधित भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत की जाएगी, जो उन्हें राज्य विधानमंडल के समक्ष रखवाएगा।

21. **Ans. [A]**

लिंकिंग प्रावधान:- अनुच्छेद 111,200.

स्पष्टीकरण:- अनुच्छेद 200 - राज्यपालों को अनुमति देने/अनुमति रोकने या राष्ट्रपति के विचार के लिए विधेयक को आरक्षित करने की शक्ति देता है।
वह विधेयक को (यदि वह धन विधेयक नहीं है) सदन द्वारा पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है।
यदि सदन/सदनों द्वारा संशोधन के साथ/बिना संशोधन के दोबारा पारित किया जाता है, तो राज्यपाल सहमति नहीं रोकेंगे।

22. **Ans. [D]**

लिंकिंग प्रावधान :- अनुच्छेद 174 ,85.

स्पष्टीकरण:- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 174 में कहा गया है कि राज्यपाल समय-समय पर सदन या राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर बैठक के लिए बुलाएगा जैसा वह उचित समझे, अधिवेशन को अहुता कर सकेगा, किन्तु एक सत्र में इसकी अंतिम बैठक और अगले सत्र में इसकी पहली बैठक में कुल 6 माह से अधिक अंतराल नहीं होगा।

अनुच्छेद 174 के खंड 2 में कहा गया है कि राज्यपाल समय-समय पर किसी भी सदन का सत्रावसान कर सकता है या विधान सभा को भंग कर सकता है। खंड 2 उसे सदन को भंग करने की शक्ति देता है।

23. **Ans. [C]**

लिंकिंग प्रावधान:- अनुच्छेद **100,101,102,190,191,192**

स्पष्टीकरण: - अनुच्छेद 190 सदस्य का पद रिक्त :-

1. दोनों सदनों के सदस्य नियुक्त हो जाए- एक सदन का पद रिक्त होगा।
2. एक से अधिक विधान मंडल पर नियुक्त हो जाये- विनिर्दिष्ट अवधि में पद रिक्त न करे सभी सदनों के पद रिक्त होंगे।
3. 60 दिन तक अनुपस्थित।
4. त्याग पत्र।

अनुच्छेद 191,192 संसद के सदस्य की निर्हरता:-

1. लाभ का पद धारण करता है।
2. न्यायालय द्वारा विकृतचित घोषित।
3. दिवालिया।
4. नागरिक नहीं।
5. किसी विधि द्वारा निरर्हित ।
6. 10वीं अनुसूची द्वारा निरर्हित।

निर्णय:- निरर्हता का निर्णय राष्ट्रपति का होगा जो निर्वाचन आयोग की राय से लेगा**।**

24. **Ans. [C]**

लिंकिंग प्रावधान:- अनुच्छेद 168,169,170, 79,80,81।

JGP (Judiciary Guidance Program) - Click Now to Enroll
AIBE Study Materials – Click here to Buy now
AGP (Advocacy Guidance Program)- Click Now to Enroll
AIBE 22 Guidance Program- Click Now to Enroll

स्पष्टीकरण:- भारत में संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम अंतर 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। इसका आशय है कि संसद की बैठक वर्ष में कम से कम दो बार होनी चाहिए।

एक वर्ष में सत्र-

1. बजट सत्र (फरवरी से मई);
2. मानसून सत्र (जुलाई से सितंबर); और
3. शीतकालीन सत्र (नवंबर से दिसंबर)।

25. Ans. [C]

लिंकिंग प्रावधान- अनुच्छेद 226 L/w 32, 139, भारत का संविधान।

स्पष्टीकरण- अनुच्छेद 226 कुछ रिट जारी करने की उच्च न्यायालयों की शक्ति से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि उच्च न्यायालय के पास उन सभी क्षेत्रों के संबंध में शक्ति होगी जिसके संबंध में वह किसी भी व्यक्ति या प्राधिकारी को, उचित मामलों में, किसी भी सरकार को, उन क्षेत्रों के भीतर निर्देश, आदेश या रिट जारी करने का अधिकार क्षेत्र रखता है।

उच्च न्यायालय द्वारा जारी की जा सकने वाली रिटें हैं-

(1) बंदी प्रत्यक्षीकरण (शरीर आपके पास हो सकता है)।
(2) परमादेश (हम आदेश देते हैं)।
(3) प्रतिषेध (निषिद्ध करना या आदेश पर रोक लगाना)।
(4) अधिकार-पृच्छा (किस अधिकार या वारंट द्वारा)।
(5) उत्प्रेषण (प्रमाणित होना या सूचित होना)।

26. Ans. [B]

लिंकिंग प्रावधान :-

1. **अनुच्छेद 32 -** उच्चतम न्यायलय द्वारा मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार।
2. **अनुच्छेद 226 -** उच्च न्यायलय द्वारा मूल अधिकारों और अन्य प्रावधानो को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार।
3. **अनुच्छेद 227 -** उच्च न्यायलय द्वारा अधीक्षण शक्ति।
4. **धारा 406 -** उच्चतम न्यायलय का मामलों व अपील को अंतरित करना - केवल एक आधार (न्याय के उद्धेश्य के लिये) व पक्षकार या महान्यायवादी के आवेदन पर (दंड प्रक्रिया संहिता, 1973)।
5. **धारा 407 -** उच्च न्यायलय द्वारा मामला व अपील का अंतरण - पक्षकारों के आवेदन, निचले न्यायलय की रिपोर्ट के अतिरिक्त स्वप्रेरणा से भी कर सकता है।

स्पष्टीकरण - अनुच्छेद 32/226 - उच्चतम न्यायलय को रिट अधिकारिता केवल मूल अधिकारों के संबंध में प्रदान की गयी है जबकि उच्च न्यायलय को रिट अधिकारिता मूल अधिकारों व अन्य प्रयोजन के लिए भी उपलब्ध है अर्थात् कहा जा सकता है उच्च न्यायलय का क्षेत्राधिकार रिट अधिकारिता के संबंध में उच्चतम न्यायलय के क्षेत्राधिकार से विस्तृत है।

27. Ans. [B]

लिंकिंग प्रावधान: भाग IX (अनुच्छेद 243-243ण), 73वां संशोधन अधिनियम, 1992, 24-4-1993 से प्रभावी भारत का संविधान।

स्पष्टीकरण- बलवंत राय मेहता समिति ने एक लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकृत स्थानीय सरकार की स्थापना का सुझाव दिया जिसे पंचायती राज के रूप में जाना जाने लगा।

पंचायती राज संस्था- पंचायती राज संस्था (PRI) भारत में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की एक प्रणाली है। ग्राम क्षेत्र स्तर पर लोकतंत्र का निर्माण करने के लिए पीआरआई को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के माध्यम से संवैधानिक बनाया गया था और इसे देश में ग्रामीण विकास का कार्य सौंपा गया था।

AIBE PAPERATHON©
Paperathon Booklet
Topic-wise PYQ Analysis, Linked Provisions, Explanations & QR Video Solutions.
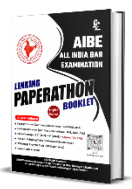
English Edition
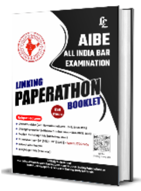
Hindi Edition
Scan this QR
E-Study Materiel
Covers all AIBE Exams [3rd(2012)-21st (2026)
Linking Support
988 774 6465 (Classes)
773 774 6465 (Publication)
Scan this QR
Order Now or visit
www.LinkingLaws.com
Link Provision
Linking Explanation
Weightage Analysis Table
[3rd (2012) - 21st (2026)]
Subject Wise Analysis
Section- Switching Table
www.LinkingLaws.com

JGP (Judiciary Guidance Program) - Click Now to Enroll
AIBE Study Materials – Click here to Buy now
AGP (Advocacy Guidance Program)- Click Now to Enroll
AIBE 22 Guidance Program- Click Now to Enroll

28. **Ans. [A]**

लिंकिंग प्रावधान :-

1. संविधान (तिहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1992
2. भाग 9 - अनुच्छेद 243-243ण ।
3. अनुच्छेद 243थ - नगरपालिका का गठन।

स्पष्टीकरण - 243ख - पंचायतों का गठन।

29. **Ans. [D]**

लिंकिंग प्रावधान :-

1. **अनुच्छेद 246 -** संसद व राज्य की विधि बनाने शक्ति।
2. **अनुच्छेद 254 -** संसद व राज्य की विधि के मध्य असंगति पर प्रक्रिया।
3. **अनुसूची 7 -** विधि बनाने की विषय वस्तु का वर्गीकरण।

स्पष्टीकरण - बिहार राज्य बनाम कामेश्वर सिंह, का वाद छद्मता के सिद्धांत से संबंधित।

30. **Ans. [B]**

लिंकिंग प्रावधान :-

1. **राज्य सूची के विषयों पर संसद द्वारा विधि बनाने संबंधी प्रावधान :-**
   - **(क)** **अनुच्छेद 249 -** राष्ट्रीय हित में।
   - **(ख)** **अनुच्छेद 250 -** जब आपात उदघोषणा प्रवर्तन में हो।
   - **(ग)** **अनुच्छेद 252 -** दो या अधिक राज्य संकल्प पारित कर सहमति दे।
   - **(घ)** अंतर्राष्ट्रिय करारों को प्रभावी बनाने के लिए।
2. **अनुच्छेद 246 -** संसद व राज्य विधानमंडलो की विधि बनाने की विषय वस्तु।
3. **अनुसूची 7 -** विधि बनाने संबंधी विषय वस्तुओं का वर्गीकरण।
4. **अनुच्छेद 107/196 -** विधि बनाने की प्रक्रिया।

स्पष्टीकरण- अनुच्छेद 249- राष्ट्रीय हित में किसी विषय पर जो राज्य सूची मे प्रगणित हो, राज्य सभा में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के दो तिहायी सदस्यों द्वारा संकल्प पारित किया जाता है, वहा उस विषय पर संसद विधि बना सकेगी, चाहे विषय वस्तु राज्य सूची मे प्रगणित हो।

31. **Ans.[B]**

लिंकिंग प्रावधान: अनुच्छेद 279 भारत का संविधान।

स्पष्टीकरण- अनुच्छेद 279 के अनुसार, “शुद्ध आगम” का अर्थ किसी भी कर या शुल्क के संबंध में संग्रह की लागत से कम आय, और उन प्रावधानों के प्रयोजनों के लिए किसी भी कर या शुल्क, या किसी भी हिस्से की शुद्ध आय किसी भी क्षेत्र में या किसी भी कर या शुल्क को भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा सुनिश्चित और प्रमाणित किया जाएगा, जिसका प्रमाण पत्र अंतिम होगा।

32. **Ans. [A]**

लिंकिंग प्रावधान: भाग XII (अनुच्छेद 264-300क) भारत का संविधान।

स्पष्टीकरण- संविधान का भाग XII वित्त, संपत्ति, अनुबंध और मुकदमों से संबंधित है। इसे 4 भागों में बांटा गया है जो इस प्रकार हैं-

(I) पहला भाग वित्त से संबंधित है और आगे 3 भागों में बांटा गया है-
- **(क)** सामान्य (अनुच्छेद 264-267)
- **(ख)** संघ और राज्यों के बीच राजस्व का वितरण (अनुच्छेद 268-281)।
- **(ग)** विविध वित्तीय प्रावधान (अनुच्छेद 282-291)।

(II) उधार लेना (अनुच्छेद 292-293)।

(III) संपत्ति, अनुबंध, अधिकार, देनदारियां, दायित्व और वाद (अनुच्छेद 294-300)।

(IV) संपत्ति का अधिकार (अनुच्छेद 300 क)।

33. **Ans. [C]**

लिंकिंग प्रावधान- अनु.279क L/w अनु.269क COI।

स्पष्टीकरण- अनु.279क माल और सेवा कर परिषद् से संबंधित है। इसे 101वें संशोधन अधिनियम, 2016 द्वारा w.e.f. 12/09/2016 से अन्तः स्थापित किया गया था। । यह प्रावधान करता है कि 101वें संवैधानिक संशोधन के प्रारंभ से 60 दिनों के भीतर राष्ट्रपति द्वारा जीएसटी परिषद् का गठन किया जाएगा।

जीएसटी परिषद् की संरचना- इसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे-

(क) संघ के वित्त मंत्री- अध्यक्ष;

(ख) संघ के राजस्व या वित्त के भारसाधक राज्यमंत्री- सदस्य;

(ग) प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट वित्त या कराधान के भारसाधक मंत्री या कोई अन्य मंत्री- सदस्य।

34. **Ans. [C]**

लिंकिंग प्रावधान: अनुच्छेद 280 L/w 264, 270, 275, 281, 243 झ, 243य भारत का संविधान।

JGP (Judiciary Guidance Program) - Click Now to Enroll
AIBE Study Materials – Click here to Buy now
AGP (Advocacy Guidance Program)- Click Now to Enroll
AIBE 22 Guidance Program- Click Now to Enroll

स्पष्टीकरण- वित्त आयोग संघ और राज्य सरकारों के बीच कुछ राजस्व संसाधनों के आवंटन के उद्देश्य से एक संवैधानिक निकाय है। यह राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 280 के तहत स्थापित किया गया था। वित्त आयोग के सदस्यों में एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य शामिल होने चाहिए जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाना चाहिए।

35. Ans. [C]
लिंकिंग प्रावधान- अनुच्छेद 299 L/w अनुच्छेद 77, 166, 361 भारत का संविधान।
स्पष्टीकरण- अनुच्छेद 299 संविदाओं से संबंधित है। यह प्रदान करता है कि किए गए सभी संविदा-
(i) संघ की कार्यकारी शक्ति के प्रयोग में, राष्ट्रपति द्वारा किए जाने के लिए अभिव्यक्त की जाएगी; या
(ii) किसी राज्य की कार्यकारी शक्ति के प्रयोग में, राज्य के राज्यपाल द्वारा किए जाने के लिए अभिव्यक्त की जाएगी।
यह राष्ट्रपति या राज्यपाल को संविधान के प्रयोजनों के लिए किए गए या निष्पादित किसी भी संविदा के संबंध में व्यक्तिगत दायित्व से छूट देता है।

36. Ans. [D]
लिंकिंग प्रावधान :-
1. **अनुच्छेद 19(1) (छ) -** व्यापार, कारोबार, वृत्ति, उपजीविका की स्वतंत्रता।
2. **अनुच्छेद 301 -** व्यापार, वाणिज्य, समागम की स्वतंत्रता।
स्पष्टीकरण - अनुच्छेद 302 व 303 में कुछ होते हुए, कोई राज्य, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से अंतर्राज्यीय व्यापार पर कर लगा सकेगा।

37. Ans. [A]
लिंकिंग प्रावधान- अनु.321 L/w अनु.315, 316, 320 COI ।
स्पष्टीकरण- अनु.321 लोक सेवा आयोगों के कार्यों का विस्तार करने की शक्ति से संबंधित है। यह प्रावधान करता है कि संसद या किसी राज्य का विधानमंडल अधिनियम द्वारा, संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा संघ या राज्य की सेवाओं के संबंध में और किसी स्थानीय प्राधिकारी या विधि द्वारा गठित अन्य निगमित निकाय या किसी लोक संस्था की सेवाओं के संबंध में भी अतिरिक्त कार्यों के प्रयोग के लिए उपबंध कर सकता है।

38. Ans. [A]
लिंकिंग प्रावधान :-
1. **अनुच्छेद 90/94 -** राज्य सभा के उपसभापति तथा लोकसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को पद से हटाना।
2. **अनुच्छेद 183/186 -** विधान परिषद् के सभापति व उपसभापति तथा विधानसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को पद से हटाना।
3. **अनुच्छेद 67 -** उपराष्ट्रपति को पद से हटाना।
4. **अनुच्छेद 61 -** राष्ट्रपति को पद से हटाना।
5. **अनुच्छेद - 124(4) -** सर्वोच्च न्यायालय के न्यायधीश को पद से हटाना।
स्पष्टीकरण- अनुच्छेद 317- लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या अन्य सदस्य को केवल कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति के आदेश से हटाया जा सकेगा जो उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित किये जाने पर उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 145 की विहित प्रक्रिया के अंतर्गत जांच के पश्चात को प्रतिवेदन करे, की अध्यक्ष या सदस्य को ऐसे आधार पर हटा दिया जाए।

39. Ans. [C]
लिंकिंग प्रावधान: धारा 4 प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम|
स्पष्टीकरण- केंद्र सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम द्वारा या इसके तहत केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण को प्रदत्त अधिकारिता, शक्तियों और प्राधिकार का प्रयोग करने के लिए एक प्रशासनिक न्यायाधिकरण की स्थापना करेगी, जिसे केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के रूप में जाना जाएगा।

40. Ans. [A]
लिंकिंग प्रावधान: अनुच्छेद 323A भारत का संविधान।
स्पष्टीकरण- ट्रिब्यूनल मूल संविधान का हिस्सा नहीं थे, इसे 42वें संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। अनुच्छेद 323-ए प्रशासनिक ट्रिब्यूनल से संबंधित है।

41. Ans. [C]
लिंकिंग प्रावधान:- अनुच्छेद 122 - न्यायलयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना।
स्पष्टीकरण - अनुच्छेद 329 - अनुच्छेद 327 या 328 के अधीन बनायी गयी विधि की विधिमान्यता, जो निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन या निर्वाचन क्षेत्रों के आवंटन से संबंधित है, किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जायेगा।

42. Ans. [C]
लिंकिंग प्रावधान :-
1. **अनुच्छेद 325 -** धर्म, मूलवंश, जाति या लिंग के आधार पर निर्वाचन नामावली मे समिल्लित किया जाने का अपात्र नहीं होना।
2. **अनुच्छेद 326 -** निर्वचन का वयस्क मताधिकार।
3. संविधान (इकसठवां संशोधन) अधिनियम, 1988 ।
4. **अध्याय 7क -** निर्वाचन संबंधी अपराध के विषय में (भारतीय दंड संहिता, 1860।
5. निर्वाचन विधि (संशोधन) अधिनियम, 1975।
स्पष्टीकरण- अनुच्छेद 326 के अंतर्गत- संविधान (61वां संशोधन) अधिनियम द्वारा संशोधन कर वयस्क मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटा कर 18 वर्ष रखी गयी।

JGP (Judiciary Guidance Program) - Click Now to Enroll
AIBE Study Materials – Click here to Buy now
AGP (Advocacy Guidance Program)- Click Now to Enroll
AIBE 22 Guidance Program- Click Now to Enroll

43. Ans. [A]
लिंकिंग प्रावधान: अनुच्छेद 340 L/w 338ख भारत का संविधान।
स्पष्टीकरण - अनुच्छेद 340 पिछड़े वर्गों के सुधार के लिए परिस्थितियों की जांच करने के लिए एक आयोग की नियुक्ति का प्रावधान करता है। राष्ट्रपति आदेश द्वारा ऐसे व्यक्तियों को शामिल करते हुए एक आयोग नियुक्त कर सकते हैं जिन्हें वह सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थितियों और पृष्ठभूमि की जांच करने के लिए उपयुक्त समझते हैं जो भारत के क्षेत्र में आते हैं।

44. Ans. [C]
लिंकिंग प्रावधान: अनुच्छेद 333 भारत का संविधान।
स्पष्टीकरण- अनुच्छेद 333: अब उस अनुच्छेद में संशोधन करने का प्रस्ताव है ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि राज्यपाल द्वारा किसी भी राज्य विधान सभा में एक से अधिक एंग्लो-इंडियन को नामित नहीं किया जाना चाहिए।

45. Ans. [B]
लिंकिंग प्रावधान: अनुच्छेद 343 L/w 344, 345, 348, 351, 8वीं अनुसूची भारत का संविधान, धारा 272, 277, 354 सीआरपीसी।
स्पष्टीकरण- अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा का प्रावधान करता है। इस अनुच्छेद के अनुसार, संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में हिंदी होगी और संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा।

46. Ans. [D]
लिंकिंग प्रावधान- अनुच्छेद 358 L/w भाग III, 359 भारत का संविधान।
स्पष्टीकरण- अनुच्छेद 358 आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 के प्रावधानों के निलंबन से संबंधित है। इसमें प्रावधान है कि युद्ध और बाह्य आक्रमण के मामलों में धारा 19 को पूरी तरह से निलंबित किया जा सकता है। किसी अलग आदेश या अनुसमर्थन की आवश्यकता नहीं है।

47. Ans. [C]
लिंकिंग प्रावधान: अनुच्छेद 352 भारत का संविधान।
स्पष्टीकरण- अनुच्छेद 352 युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण आपातकाल की उद्घोषणा से संबंधित है। इसे लोकप्रिय रूप से 'राष्ट्रीय आपातकाल' के रूप में जाना जाता है। L/w Article 356,360 of COI.

1.	आपातकाल की उद्घोषणा - **अनुच्छेद 352**	2.	चुनाव आयोग-**अनुच्छेद 324**
3.	संघ लोक सेवा आयोग-**अनुच्छेद 315**	4.	वित्त आयोग-**अनुच्छेद 280**

48. Ans. [A]
लिंकिंग प्रावधान: अनुच्छेद 261 भारत का संविधान।
स्पष्टीकरण- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 261 में कहा गया है कि संघ और प्रत्येक राज्य के सार्वजनिक कृत्यों, अभिलेखों और न्यायिक कार्यवाहियों के लिए भारत के पूरे क्षेत्र में पूर्ण विश्वास और श्रेय दिया जाएगा।
अनुच्छेद 148 - भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक।
अनुच्छेद 256- राज्यों और संघ की बाध्यता।
अनुच्छेद 261 - सार्वजनिक कार्य, अभिलेख और न्यायिक कार्यवाही।
अनुच्छेद 368 - संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसकी प्रक्रिया।

49. Ans. [A]
लिंकिंग प्रावधान :- अनुच्छेद 368 COI ।
स्पष्टीकरण – वाद- वामन राव बनाम भारतीय संघ (1981)- यह माना गया था कि संविधान का मूल ढाँचा, अनुच्छेद 368 के तहत शक्ति के अभ्यास में संविधान-संशोधन द्वारा, नष्ट या क्षतिग्रस्त नहीं किया जा सकता ।

50. Ans. [B]
लिंकिंग प्रावधान:- अनुच्छेद 371ग - मणिपुर राज्य के संबंध में विशेष प्रावधानों से संबंधित है।
महत्वपूर्ण बिंदु :-
भारत के संविधान का भाग XXI कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधानों से संबंधित है।
प्रावधान अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान हैं।
1. **अनु. 371 –** महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के संबंध में विशेष प्रावधान।
2. **अनु. 371क –** नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान।
3. **अनु. 371ख –** असम राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान।
4. **अनु. 371ग –** मणिपुर राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान।
5. **अनु.371घ –** आंध्र प्रदेश राज्य और तेलंगाना राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान।

स्पष्टीकरण: - भारतीय संविधान का अनुच्छेद 371ग मणिपुर राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान से संबंधित है। वे इस प्रकार हैं: यह अनुच्छेद 1971 के 27वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था।

JGP (Judiciary Guidance Program) - Click Now to Enroll
AIBE Study Materials – Click here to Buy now
AGP (Advocacy Guidance Program)- Click Now to Enroll
AIBE 22 Guidance Program- Click Now to Enroll

Advocacy Booklet

is available at

www.LinkingLaws.com >> Linking Publication

STEPS TO ADVOCACY

Link LL.B with Practice

What You'll Learn

- English Edition
- Practical Advocacy Strategies
- Courtroom Legal Practice
- Essential Professional Skills
- From Beginner to Established Practice
- Role of a Senior Advocate
- Building a Sustainable Legal Career

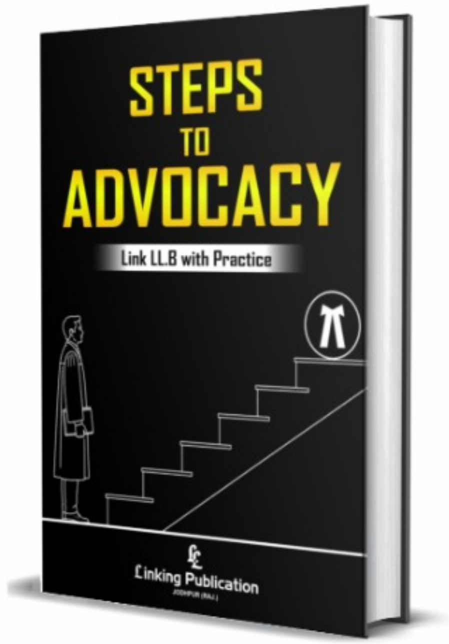

ADVOCACY GUIDANCE PROGRAM (AGP)

Validity - 03 Months

Complete Syllabus Coverage

Civil Court Practice | Criminal Court Practice | Cyber Law Practice | Dual Mode Learning | Legal Personality Development | Structured 3 Volumes

Linking Support
988 774 6100 (Classes)
773 774 6465 (Publication)

Scan this QR
ENROL NOW

Scan this QR
Order Now or visit
www.LinkingLaws.com

E-Study Material for Judiciary and Law Exams
is available at **Linking App.**